RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

मध्य प्रदेश में औद्योगीकरण का विकास

Raj Kumar Raidas

Research scholar, Commerce, Awadhesh Pratap Singh Vishwavidyalaya Rewa (M.P.)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
औद्योगिक विकास प्रशासनिक अनुपालन

ABSTRACT

शोध अध्ययन के दौरान यह एक महत्वपूर्ण तथ्य शोधार्थी के सामने आया कि प्रदेशों के तीव्र औद्योगीकरण में प्रदेश सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु नीतियाँ, नियमन निर्माण करती है। नीतियों के अनुपालन व सहयोग हेतु चुस्त व तत्पर प्रशासनिक तंत्र गठित करती है। प्रदेश में औद्योगिक विकास में प्रदेश की औद्योगिक नीतियाँ व उद्योगों को निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होती है। मध्यप्रदेशें का इस संदर्भ में उदाहरण ले सकते है। मध्यप्रदेश सरकारों ने प्रदेश में तीव्र औद्योगीकरण को प्राप्त करने के लिये औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया इन औद्योगिक नीतियों के अनुपालन हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया।

परिचय

औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास आधुनिक युग में आर्थिक विकास का पर्यायवाची सा बन गया है। आज विश्व के प्रायः समस्त देश औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं सम्पन्नता का केवल आधार ही नहीं बल्कि उसके आर्थिक विकास का मापदण्ड माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता बहुत अधिक है और स्पष्ट भी। वास्तव में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अभाव में देश के आर्थिक विकास का कार्य अधूरा ही रहेगा। उद्योंगों के समुचित विकास के बिना लोगों की आय में अर्थपूर्ण एवं नियमित रूप से वृद्धि लाना सम्भव नहीं है। औद्योगीकरण के फलस्वरूप अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर देश के विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता या महत्व की कल्पना आसानी से की जा सकती है और साथ ही साथ हम इस बात को भली प्रकार समझ सकेंगे कि वर्तमान समय में इस ओर क्यों अधिका–अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

वस्तुतः औद्योगीकरण आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं से ग्रसित अनेक पिछड़े हुए राष्ट्रों के नव निर्माण के लिए आशा की एक किरण के समान है जो उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अनेक ऐसे राष्ट्र जो भौतिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी विपन्न है, औद्योगीकरण के द्वारा अपने विपुल साधनों का भरपूर उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ा सकते है और इस प्रकार अन्ततः अपने नागरिकों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सन्तोषजनक जीवन स्तर प्रदान कर सकते हैं। विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वे सब औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अभी नहीं आते है ं लेकिन विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके है वे सब औद्योगिक विकास के द्वारा ही अपने आर्थिक विकास क लिए प्रयत्नशील हैं। पिछले तीन दशकों में अनेक विकासशील देशों के द्वारा औद्योगीकरण की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गयी है।

साहित्य का पुनरावलोकन

जनसत्ता (2010) ''नदी का जीवन''। यह लेख औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के विकास के चलते नदियों के प्रदूषण, प्राकृतिक संसाध्नों के विनाश को अभिव्यक्ति करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड द्वारा चलाई गई नदियों से संबंध्ति नीतियों की असपफलता पर ध्यान आकर्षित करता है। इस लेख से हमें यह ज्ञात होता है कि जो नदी मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख कारण रही आज उसी का अस्तित्व खतरें में है। अतः इस पर विचार न करना मानव अस्तित्व को खतरे में डाला होगा।

अमित भादुड़ी (2011) फविकास का आतंक गरीबी बेरोजगारी विषमता विस्थापनय। प्रस्तुत पुस्तक परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए यह सवाल उठाती है कि यह कैसा विकास है जो देश की तीन चौथाई आबादी का` बस इतना दे रहा है कि वे किसी तरह जिंदा रह सके? यह कैसा विकास है जिसमें आर्थिक दो अंकों की दर्ज होती है पिफर भी रोजगार दशमलब में बढ़ावा है यह कैसा विकास है कि एम.ए. और इंजीनियरिंग पास नौजवान क्लर्क, दरबान, चपरासी और रेलवे गैंगमैन जैसी नौकरियों के लिए भी तैयार है। जहाँ एक–एक नौकरी के लिए मिलों लम्बी लाईन बेरोजगारों की लगी है। यह कैसा विकास है कि खाने–पीने और सेहत के लिहाज से देश के लोगों से बेहतर हालत में यहाँ के चूहे है ं ;खाद्य विज्ञानी और सेंट्ल पूफड टेक्नालॉजी रिसर्च इंस्टीच्यूट के पूर्व निदेशक ए वी पार्पिया का बयान, द हिन्दू 12 अगस्त, 2010, पेज 6 यह किताब इन तमाम सवालों पर गहराई से प्रकाश डालती है और यह बताती है कि तेज रफ़्तार आर्थिक विकास का पर्याय नहीं है। यह किताब बताती है कि विकास दरअसल क्या है? भारत जैसे देश के लिए कैसे

RRIJM 2015, All Rights Reserved

विकास की आवश्यकता है। हमारे सामने विकास के कौन से वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। इन मसलों से जुझने के क्रम में यह किताब भारत की 'राजनीतिक–आर्थिक' विकास की तस्वीर भी पेश करती है।

रघुराम (2005) ने कर्नाटक के लघु उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया। वर्तमान में वैश्विक प्रतियोगी वातावरण में भारतीय लघु उद्योग के सामने अनेक बाधाएं खड़ी हो गई है। इसके बावजूद भारतीय लघु उद्योग विकास कर रहे है ं। सरकार कच्चा माल आवंटन में प्राथमिकता देकर तथा सस्ते ऋण उपलब्ध कराने की नीति बनाकर लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। आर्थिक सुधारों के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी लघु उद्योगों पर पड़ रहे हैं। बड़े उद्योग गुणवत्ता की शर्त पर लघु व मध्यम उद्यमों से अपने उत्पाद का निर्माण करवा रहे है।

मेहराणा एवं बाघबनपुर, (2016) ने औद्योगिक एवं कृषि निर्यात का विकासशील देशों के 1970 से 2014 की अवधि में हुए आर्थिक विकास में योगदान का अध्ययन किया है। इसके लिए 34 विकासशील देशों के अध्ययन अवधि के सकल घरेलू उत्पाद एवं निर्यात संबंधी आँकड़ों का संकलन कर पैनल डेटा एप्रोच विधि से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते है ं कि औद्योगिक निर्यात और आर्थिक वृद्धि के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सह–संबंध है, लेकिन कृषि निर्यात और आर्थिक वृद्धि के मध्य कमजोर संबंध पाया गया। इसी के साथ–साथ यह भी देखा गया कि कुल सार्वजनिक उपभोग एवं सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य सकारात्मक एवं धनात्मक सह–संबंध है।

नीलम सिंह, (2006) ने आटो पार्ट्स की लघु व मध्यम उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। उनके अध्ययन का निष्कर्ष है कि आर्थिक सुधारों के पश्चात् वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई है। लघु व मध्यम उद्यमों (SMEs) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। सरकारी क्रय में प्राथमिकता देकर सरकार लघु उद्योगों की सहायता कर सकती है।

औद्योगिक विकास अथवा औद्योगीकरण का अर्थ

औद्योगीकरण विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को समाप्त करके किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को नई दिशा प्रदान करती है। श्री ब्राईस के अनुसार– "विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अन्ततः एक व्यापक भूमिका का निर्वहन करना होता है।

औद्योगीकरण के इस दौड़ में विश्व के सभी देश सम्मिलित हैं, जिसमें कुछ आगे बढ़ चुके है तथा अनेक देश अभी भी औद्योगीकरण में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे है रोचक बात यह है कि विकसित देशों में भी औद्योगीकरण के अधिकाधिक ऊँचे स्तर तक पहुँचने की एक होड़–सी लगी हुई है। इन विकसित देशों में अमेरिका व रूस का नाम उल्लेखनीय है। अतः औद्योगीकरण आज आधुनिक युग का एक धर्म बन चुका है जिसका पालन करने के अतिरिक्त कोई आ ैर विकल्प नहीं है।

औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास का आर्थिक विकास में महत्व

किसी देश की आर्थिक दशा सुधारने अथवा आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास सर्वोत्तम उपाय है। अल्प विकसित देशों की समस्याओं के निराकरण में तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि औद्योगीकरण के द्वारा ही किसी देश के उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा केवल प्राकृतिक साधनों का ही नहीं बल्कि मानवीय साधनों का भी अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग हो सकता है, क्योंकि औद्योगीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्तियों की कुशलता में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है।

भारतीय योजना आयोग ने औद्योगिक विकास के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है–"औद्योगिक विकास की व्यूह रचना में संरचनात्मक, विविधीकरण, आधुनिकीकरण एवं स्वावलम्बन के उद्देश्यों की पूर्ति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। योजना आयोग की भाँति कृषि आयोग ने औद्योगीकरण के लाभ के सन्दर्भ में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि–''औद्योगीकरण समस्त राष्ट्र के लिए अत्यन्त लाभदायक होगा क्योंकि यह पूँजी के नये साधनों को उत्पन्न करेगा, पूँजी की बचत को बढ़ावा देगा सरकार की आय में वृद्धि करेगा, श्रमिकों को जीविका प्रदान कर सकेगा, कृषि के अनिश्चित लाभों पर राष्ट्र की अत्याधिक निर्भरता में कमी करेगा और राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा।

औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास की समस्याएँ

औद्योगीकरण मात्र यांत्रिक साधनों एवं तकनीकी सुविधाओं का ही परिणाम नहीं है। इसकी सफलता के लिए आर्थिक अपेक्षाओं के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक तत्वों का अनुकूल होना भी अत्यन्त आवश्यक है। अल्प विकसित देशों में औद्योगीकरण की अनेक बाधाएं हैं जो वहाँ सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। इन बाधाओं को दूर करके विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण एक अत्यन्त कठिन तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

आर्थिक आधारिक संरचना का अभाव

आर्थिक आधारिक संरचना का अभाव र्थिक आधारिक संरचना का अभाव किसी देश में औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास का कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सकता है जब तक उस देश की आर्थिक आधारिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित न हो। आर्थिक संरचना में यातायात के साधन, ऊर्जा के साधनों की व्यवस्था, बीमा एवं साख बैंकिंग सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं, मशीनों की मरम्मत की सुविधाएं आदि सम्मिलित की जाती हैं। स्पष्ट है कि यातायात के साधनों के अभाव में उद्योगों की स्थापना कठिन हो जाती है। क्योंकि कच्चे माल को औद्योगिक केन्द्र तक लाने में, उत्पादित माल के बाजारों तक ले जाने में तथा श्रमिकों को दूर–दूर तक आकर्षित करने के लिए यातायात के कुशल तथा सस्ते साधन उपलब्ध होने चाहिए। शक्ति के साधन यंत्रों को गति प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना शक्ति के साधनों के अभाव में असम्भव ही है।

पूँजी का अभाव

पूँजी का अभाव अल्प विकसित अथवा अर्द्ध–विकसित देशों में व्यापक निर्धनता के कारण पूँजी का संचयन नहीं हो पाता, आय का स्तर ऊँचा होने पर लोगों की बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है जबकि पूँजी को औद्योगीकरण का आधार कहा गया है। बेंगामिन हिगिन्स के शब्दों में– "पूँजी का संचय आर्थिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। अर्थव्यवस्था चाहे अमेरिका की भांति पूँजीवादी हो अथवा रूस या चीन की भांति साम्यवादी, आर्थिक विकास बिना पूँजी के संचय के सम्भव हो ही नहीं सकता।" परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं प्राप्त हो पाता है प्रतिवर्ष जितनी भी नयी पूँजी का सृजन होता है वह प्रति व्यक्ति पूँजीगत सम्पत्ति के स्तर को बनाये रखने में ही समाप्त हो जाती है।

बाजार की अपूर्णताएँ एवं अपर्याप्तताएँ

बाजार की अपूर्णताएं एवं अपर्याप्तताएं भी औद्योगिक विकास में बड़ी समस्या उत्पन्न करती हैं। बाजार की अपूर्णताओं से तात्पर्य अविकसित परिवहन के साधनों का रहना है। अल्प विकसित देशों मे बाजारों में अपूर्णताएं रहती हैं, क्योंकि यहाँ परिवहन के साधन अविकसित होते हैं। इसी कारण निर्मित माल बाजारों तक पहुँचाने तथा कच्चा माल उद्योगों तक ले जाने में कठिनाई होती है और जब वस्तुएं बाजारों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती हैं तो, बहुत वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं तथा बाजार में पूर्ति कम रहती है। अतः औद्योगिक विकास में रूकावट उत्पन्न हो जाती है।

निष्कर्ष

राज्यों के औद्योगिक विकास में निवेशक सम्मेलनों की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध अध्ययन कर शोध समस्या के समाधान हेतु खोज प्रक्रिया सम्पन्न की गयी। इस प्रक्रिया में शोधार्थी द्वारा शोध विषय पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकें, समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री, निवेशक सम्मेलनों में उपस्थिति प्रदेशों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन, प्रशासनिक तंत्र की संरचना आदि जानने के विभिन्न प्रयत्न किये। शोध अध्ययन के दौरान शोध विषय से संबंधित कुछ तथ्य शोधार्थी के सामने आये। ये तथ्य ऐसे तथ्य है जिन्हें शोध विषय के सार तत्व कह सकते है व जो भविष्य में प्रदेशों में होने वाले निवेशक सम्मेलनों, प्रदेश के औद्योगिक विकास को तीव्र करने हेतु किये जाने वाले प्रयत्नों आदि को प्रभावशील बनाने हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।देशों के सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है उद्योग। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश प्रोत्साहित कर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कर अनियोजन, पिछड़ापन, कम प्रति व्यक्ति आय जैसी समस्याओं को समाप्त कर राज्य अपने यहाँ आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित कर सकते है।

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. चिन्मय मिश्र नर्मदा की छाती पर एक नया पत्थर, ;दिल्ली : वर्ष–33, अंकः 17, 16–30 अप्रैल, 2010, पृ.सं.10–11.
2. अमित भादुड़ी, विकास का आतंक गरीबी बेरोजगारी विषमता विस्थापन, ;पटनाः पिफलहाल, 2011)
3. मेहराणा, एम0 एण्ड बाघबनपुर, जे0. 2016. ''दि कंट्रीब्यूशन ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ : दि केस ऑफेवलपमेंट कंट्रीज'', वर्ल्ड साइंटिफिक न्यूज, वा0–46, पृ0 100–111
4. Singh, Neelam (2006) : "Globalization and Auto Component SME's in India", in Agrawal, Manmohan and Ray, Amit Shevon (ed.) " Globalization and the Millenium Development Goals; Negotiating Challenge", Social Science Press, New Delhi. Page 147-172.
5. घोष, अरविन्द (2004), ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जॉन फूँकने के प्रयास'', योजना, अंक 5 (अगस्त), पृष्ठ 38–42।
6. कुरियन, बी. (2004), ''दुग्ध उत्पादन ग्रामीण विकास का एक साधन'', योजना, अंक 5 (अगस्त), पृष्ठ 11–14।
7. शिवरामन, एन0. 2010. भारत के मुख्य कृषि उत्पादों की निर्यात–आपूर्ति एवं आयात–मांग का एक अर्थमितीय विश्लेषण, पी–एच0डी0 (कृषि अर्थशास्त्र) शोध–ग्रन्थ, इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली.
8. भट, टी0पी0. 2011. स्ट्रेक्चरल चेंजेज इन इण्डियाज फॉरेन ट्रेड, इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपेंट, नई दिल्ली, नवंबर. पृ0 18.
9. बिमल जालान, भारत का आर्थिक संकट और समाधन, ;नयी दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011द्ध
10. अरूंधति रॉय, कठघरे में लोकतंत्रा, ;नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2012)

RRIJM 2015, All Rights Reserved